सुरेंद्र पासवान

बनाम

झारखंड राज्य

नवंबर 28, 2003

[दोराईस्वामी राजू और अरिजीत पासायत, जे. जे.]

आपराधिक विचारण :

चश्मदीद गवाहों ने आरोपी द्वारा मृतक पर गोली चलाते हुए देखा था, बाद में मृतक के शव में एक गोली मिली थी परंतु गोली को रासायनिक परीक्षण के लिए नहीं भेजा गया- क्या- यह अभियोजन पक्ष के लिए घातक होगा- आयोजित नहीं- जब चश्मदीद गवाहों द्वारा दिए गए सबूत विश्वसनीय, ठोस और भरोसेमंद हो, केवल इसलिए कि गोली को बैलिस्टिक के लिए नहीं भेजा गया था, यह चश्मदीद गवाह की गवाही के मूल्य से अधिक नहीं होगा।

इसी घटना में अभियुक्त के शरीर पर आईं मामूली चोटें अदालत के समक्ष संज्ञान में नहीं लाया गया। चिकित्सा साक्ष्य चाहे घातक हो या नहीं लेकिन यह एक अपरिवर्तनीय नियम नहीं है कि अभियोजन पक्ष को चोटों की व्याख्या करनी होगी। अभियुक्त द्वारा समर्थित जब अभियोजन पक्ष एक निश्चित मामले के साथ आता है कि अपराध अभियुक्त द्वारा किया गया है और अपने मामले को किसी भी उचित संदेह से परे साबित करता है, तो अभियोजन पक्ष के लिए फिर से यह समझाना शायद और भी आवश्यक हो जाता है कि अभियुक्त को कैसे और किन परिस्थितियों में चोटें लगी हैं।

मृतक और आरोपी एक ही ट्रेड यूनियन में थे। मृतक एक अन्य संघ में शामिल हो गए। जब मृतक और उसका बेटा पीडब्लू-4 चाय लेने पीडब्ल्यू- 5 के पास की चाय की दुकान पर लेने गए थे, जहां पीडब्लू- 1 और पीडब्लू- 2 उस दुकान के पास बैठे थे। अचानक वहां चार आदमी रोड के किनारे से आए। ए 3 पीडब्लू- 4 व मृतक के पास आया और निर्देशित किया कि मृतक पर हमला होने चाहिए। यह सुनकर अपीलार्थी ने अपनी कमर से पिस्तौल निकाली और मृतक पर गोली चला दी। गोली मृतक की बाई आंख में लगी, जिसके परिणामस्वरूप वह जमीन पर गिर गया। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया।

चक्षुदर्शी के साक्ष्य पर भरोसा करते हुए, निचली अदालत ने आरोपी व्यक्तियों को अपराधी ठहराया। अपील उच्च न्यायालय में दायर की गई। ए-1 की अपील लंबित रहने के दौरान उसकी मृत्यु हो गई, ए-2 और ए-3 को संदेह का लाभ देते हुए उन्हें बरी कर दिया गया। हालांकि उच्च न्यायालय द्वारा अपीलार्थी की दोषसिद्धि की पुष्टि की गई थी। इसलिए याचिका उच्चतम न्यायालय में दायर की गई थी।

अपीलार्थी द्वारा यह तर्क दिया गया था कि यद्यपि अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि एक गोली चलाई गई थी, जांच अधिकारी के द्वारा जांच के दौरान साक्ष्य के क्रम में

यह भी कहा गया था कि उसने एक छर्रा बरामद किया था;जबकि मृतक के शरीर पर जो गोली मिली थी, उसे डॉक्टर द्वारा निकाला गया था, जिसे डॉक्टर द्वारा पुलिस को सौंप दिया था और उसे रासायनिक जांच के लिए नहीं भेजा गया था, अभियुक्तगण पर लगी चोटों को अभियोजन पक्ष द्वारा स्पष्ट नहीं गया और जांच निष्फल की गई थी क्योंकि अपीलार्थी की चिकित्सा रिपोर्ट भी एकत्र नहीं की गई थी और जब्त की गई गोली को बैलिस्टिक जांच के लिए भी नहीं भेजा गया था जो अभियोजन मामले के लिए घातक था।

राज्य द्वारा यह तर्क दिया गया था कि तीन चश्मदीद गवाहों ने विशेष रूप से घटना स्थल, हमले के तरीके, और पूरे परिदृश्य का विस्तृत विवरण दिया, निचली अदालत के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने सबूत को विश्वसनीय, ठोस और भरोसेमंद पाया था यह केवल इसलिए कि गोली को रासायनिक जांच के लिए नहीं भेजा गया था, यह एक ऐसा कारक नहीं होगा जो चश्मदीद गवाहों की गवाही के मूल्य से अधिक होगा।

अपील को खारिज करते हुए, अदालत ने यह पाया कि -

1. अभियोजन पक्ष द्वारा चोटों के बारे में स्पष्टीकरण न देने से अभियोजन पक्ष के मामले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा केवल जहां अभियुक्त को मामूली या सतही चोटें लगी थीं या जहां सबूत इतने स्पष्ट और दृढ़ थे, इतने स्वतंत्र और उदासीन, इतने संभावित, सुसंगत थे और यह श्रेयस्कर है कि यह चोटों की व्याख्या करने के लिए अभियोजन पक्ष की ओर से चूक के प्रभाव से अधिक है। अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा प्राप्त चोटों की व्याख्या करने के लिए सभी मामलों में अभियोजन से अपेक्षा नहीं की जाती है। अभियुक्त व्यक्तियों की चोटों के बारे में अभियोजन पक्ष के गवाह से सवाल करना बचाव पक्ष का काम है। जब ऐसा नहीं किया जाता है, तो अभियोजन पक्ष के गवाह के लिए किसी भी चोट की व्याख्या करने का कोई अवसर नहीं होता है। एक ही घटना में अभियुक्त द्वारा दी गई चोट प्रत्येक मामले में उत्पन्न नहीं हो सकती है। जब अभियोजन पक्ष एक निश्चित साक्ष्य के साथ आता है और यह साबित करता है कि अपराध अभियुक्त द्वारा किया गया और बिना किसी संदेह के प्रमाणित करता है तो बिना किसी भी उचित संदेह से परे, अभियोजन पक्ष के लिए यह फिर से समझाना शायद और भी आवश्यक हो जाता है कि कैसे और किन परिस्थितियों से अभियुक्त व्यक्ति को चोटें लगी हैं। ऐसा केवल तब नहीं होता जब चोटे सरल या सतही प्रकृति की होती है। प्रस्तुत मामले में, अभियुक्तों पर मामूली और सतही चोटों से बहुत कम मदद मिलती है, उन्हें अभियोजन मामले की सत्यता पर संदेह करने के लिए।

(328 ई-एच 329.प.बी)

1.2. चोटों की गैर व्याख्या अधिक महत्वपूर्ण हो सकती है जहाँ बचाव पक्ष एक संस्करण देता है, जो अभियोजन पक्ष के साथ प्रायिकता में अहम रोल अदा करता है। लेकिन जहां सबूत स्पष्ट है, ठोस और विश्वसनीय है और जहां अदालत सच्चाई को उससे अलग कर सकती है। केवल यह तथ्य कि अभियोजन पक्ष द्वारा चोटों को स्पष्ट नहीं किया है। परिणामस्वरूप इस तरह के साक्ष्य से पूरे मामले को अस्वीकार करने का एकमात्र आधार नहीं हो सकता है।

[328 सी.डी]

मोहन राय और भरत राय बनाम बिहार राज्य, [1968] 3 एससीआर 525. लक्ष्मी सिंह और वगैरह बनाम बिहार राज्य, [1976] 4 एस. सी. सी. 394 और विजयी सिंह वगैरह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, ए. आई. आर. (1990) एस. सी. 1459, पर भरोसा।

सुखवंत सिंह बनाम पंजाब राज्य, A.I.R (1995) एससी 1601: रामलगन सिंह बनाम बिहार राज्य, A.I.R (1972) एससी 2593 और हरे कृष्ण सिंह और वगैरह बनाम बिहार राज्य, A.I.R (1988) एस. सी. 863, संदर्भित किया।

2. जहाँ तक खाट से खून न एकत्रित का संबंध है, जाँच अधिकारी ने कहा कि उसने घटना स्थल पर खून के धब्बे मिट्टी पर पाये और उसे जब्त कर लिया। केवल इसलिए कि इसे रासायनिक परीक्षण के लिए नहीं भेजा गया, यह जांच में एक दोष हो सकता है लेकिन यह नहीं कि यह चश्मदीद गवाहों के साक्ष्य के मूल्य को नष्ट कर देता है। जाँच अधिकारी को खाट पर खून नहीं मिला। निचली अदालत और उच्च न्यायालय ने इस पहलू का विश्लेषण किया। उनके द्वारा यह पाया गया है कि गोली लगने के बाद मृतक आगे झुक गया और जो भी खून निकला वह धरती पर गिर गया। [329- सी.डी]

3. अभियोजन पक्ष का मामला केवल गोली को रासायनिक परीक्षण के लिए नहीं भेजे जाने के कारण विफल नहीं होगा। (329 - ई)

सुखवंत सिंह बनाम पंजाब राज्य, **ए. आई. आर. (1995) एस. सी. 1601, विशिष्ट।**

4. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अभियोजन पक्ष के गवाहो को किसी भी प्रकार का सुझाव नही दिया गया कि चोटे जो अभियुक्त अपीलार्थी को आ गई थीं वो उनके द्वारा बताए गए तरीके से आईं थीं, जैसा कि धारा 313 Cr.P.C के तहत बयान में पहली बार कहा गया है। [329-जी]

5. जहाँ तक गोली और छर्रे से संबंधित भ्रम का संबंध है। डॉक्टर के साक्ष्य द्वारा यह स्पष्ट किया गया है, जिसने स्पष्ट रूप से कहा था कि मृतक के शरीर पर केवल एक चोट थी और मृतक के शरीर पर कहीं भी कोई अन्य चोट नहीं पाई गई थी। इसलिए, जांच अधिकारी द्वारा बरामद किए गए छर्रे से कोई चोट नहीं लगी है, यह डॉक्टर द्वारा स्पष्ट किया गया है। जाँच अधिकारी ने स्पष्ट किया था कि गोली डॉक्टर द्वारा पुलिस अधिकारियों को दी गई थी, जिसे शुरूवात में पेश नहीं किया गया क्योंकि यह मालखाने में थी, लेकिन बाद में गवाह को पनः बुलाया गया और उसे अदालत में पेश किया गया।

[329- एच: 330-ए-बी]

आपराधिक अपील क्षेत्राधिकारः आपराधिक अपील सं 20/2003.

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची के आदेश, निर्णय दिनांकित-22.4.2002 Crl.A.No.112/1996(R).

ए. शरण, श्रीमती पूनम सिन्हा, समीर अली खान और इरशाद अहमद अपीलार्थी के लिए।

अनिल कुमार झा प्रत्यर्थी की ओर से ।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया

अरिजीत पसायत, जे. एक बरहन दास (इसे मृतक कहा जाएगा) मृतक ने अपनी वफादारी को एक ट्रेड यूनियन से दूसरे में बदलने के लिए कीमत चुकाई और सुरेंद्र (इसे आरोपी कहा जाएगा) को उसकी जान लेने में सहायक बताया गया। चार व्यक्तियों पर भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में 'आई. पी. सी.) की धारा 34. के साथ पठित धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के आरोप में मुकदमा चलाया गया। निचली अदालत ने उन्हें तदनुसार दोषी ठहराया। यह मामला झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष अपील में किया गया था, जिसने विवादित आदेश को अभियुक्त अपीलार्थी द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया और कहा कि ट्रायल कोर्ट द्वारा उसके खिलाफ आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत आरोप लगाए गए हैं, और उसे आरोपी संख्या-4 साबित किया गया है। उच्च न्यायालय में अपील के लंबित रहने के दौरान केदार दुसाद (ए-1) की मृत्यु हो गई। चंद्रिका दास (ए-2) और कृष्ण कुमार (ए-3) को संदेह का लाभ दिया गया और उन्हें बरी करने का आदेश दिया गया।

मुकदमे के दौरान अभियोजन संस्करण इस प्रकार है:-

मृतक और उसका बेटा सत्येंद्र दास (पीडब्लू-4) सुबह लगभग 9:30 बजे दिनांक 01.08.1995 को सियाराम (पीडब्लू-5) की दुकान के पास चाय पीने गया था। हीरा साओ (पीडब्लू- 1) और रवींद साओ (पीडब्लू-2) भी दुकान के पास बैठे थे। अचानक चारों आरोपी सड़क के किनारे से आ गए। अभियुक्त कृष्ण कुमार सूचना देने वाला (पीडब्लू-4) और मृतक के पास आया और निर्देश दिया कि मृतक पर हमला होना चाहिए। ऐसा सुनकर आरोपी अपीलार्थी सुरेंद्र ने अपनी कमर से पिस्तौल निकाली और मृतक पर गोली चला दी। गोली मृतक की बाई आंख में लगी। गोलीबारी के बाद चारों आरोपी भाग गए। गोली लगने पर,मृतक नीचे गिर गया और बेहोश हो गया। सूचना देने वाला आस पास के लोगो की मदद से उन्हें पास के अस्पताल ले गए जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस स्टेशन में दी गई जानकारी के अनुसार जाँच शुरू की गई; चारों अभियुक्त व्यक्ति कटरास कोलियरी में काम करते थे। मृतक मजदूर नेता था। चूंकि उसने उस संघ को छोड़ दिया था जिससे आरोपी व्यक्ति संबंधित थे और दूसरे संघ में शामिल हो गया था, इसलिए आरोपी व्यक्तियों को इस बात गुस्सा था और इस वजह से हत्या हुई है। जाँच पूरी होने के बाद आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। अभियुक्त व्यक्तियों ने गलत निहितार्थ का अनुरोध किया।

चश्मदीद गवाहों के साक्ष्य पर भरोसा रखते हुए, निचली अदालत ने आरोपी व्यक्तियों को दोषी ठहराया और उच्च न्यायालय ने भी दोषसिद्धि को केवल अभियुक्त अपीलार्थी के संबंध में बनाए रखा । इस याचिका में उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी गई है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि सूचना देने वाले द्वारा दी गई जानकारी को प्रथम सूचना रिपोर्ट के रूप में नहीं माना जा सकता है क्योंकि पुलिस अधिकारियों को घटना के बारे में पहले ही जानकारी मिल चुकी थी। इसलिए, दिए गए बयान को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में 'Cr.P.C.') की धारा 162 के प्रावधानों से प्रभावित किया गया था। घटना स्थल को भी बदल दिया गया है क्योंकि उस खाट से कोई खून नहीं बरामद किया गया था जहां मृतक कथित तौर पर हमले के समय बैठा था। क्योंकि तथाकथित चश्मदीद गवाहों ने कहा था कि खाट पर खून गिरा था। हालांकि, अभियोजन पक्ष का मामला वह एक गोली जो चलाई गई थी। जांच अधिकारी द्वारा अदालत में उनके बयान में कुछ चरणों में कहा गया है कि उन्होंने एक पेलेट बरामद किया है । पैलेट और गोली अलग-अलग चीजें हैं । अभियोजन पक्ष ने वास्तविक परिदृश्य

को दबा दिया है और यह विभिन्न प्रकार के गोला-बारूद से स्पष्ट है। मृतक के शरीर में जो गोली मिली थी, उसे डॉक्टर ने निकाला और उसे पुलिस अधिकारियों को सौंप दिया। उसे रासायनिक परिक्षण के लिए नहीं भेजा गया था। इसलिए दोषसिद्धि को बरकरार नहीं रखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त, जाँच अधिकारी ने स्वीकार किया था कि अभियुक्त अपीलार्थी घटनास्थल से लगभग 50 फीट की दूरी पर घायल और अचेतावस्था (बेहोश अवस्था) में पाया गया था। जिसके कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता पड़ी। अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त पर लगी चोटों को स्पष्ट नहीं किया और जांच पूरी तरह से स्पष्ट नहीं थी जैसा कि इस स्वीकृत तथ्य से स्पष्ट है कि अभियुक्त- अपीलार्थी की चिकित्सा रिपोर्ट भी एकत्र नहीं की गई थी और जब्त की गई गोली रासायनिक परीक्षण के लिए नहीं भेजी गई थी। *सुखवंत सिंह बनाम पंजाब राज्य* ए. आई. आर. (1995) एस. सी. 1601 मामले में इस न्यायालय के फैसले पर मजबूत निर्भरता रखी गई थी और इन्ही तथ्यों पर जोर दिया गया है। 313 दंड प्रक्रिया संहिता के बयान में भी अभियुक्त अपीलार्थी ने एक निश्चित रुख अपनाया था कि मृतक द्वारा एक गोली चलाई गई थी जो उसे नहीं लगी और मृतक ने सत्येंद्र दास, मुन्ना दास, हीरा साओ और रवींद्र साओ ने उस पर हमला किया, जिससे वह बेहोश हो गया। आरोपी अभिलार्थी को लगी चोटे भी गंभीर प्रकृति की थी इसीलिए बचाव पक्ष का तर्क अधिक संभावित था और इसलिए दोषसिद्धि को दरकिनार कर दिया जाना चाहिए, यही उसकी याचिका थी।

जवाब में, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि तीन चक्षुदर्शी साक्षी द्वारा घटना के स्थान के संबंध में व पूरे परिदृश्य का विस्तृत विवरण दिया गया साथ ही साथ हमले का तरीका भी पूर्ण रूप से बताया गया। निचली अदालत और उच्च न्यायालय ने अपने साक्ष्यों का विश्लेषण किया है और उन्हें विश्वसनीय, ठोस और भरोसेमंद पाया है। यह स्थिति होने के कारण, इस अपील में हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है। इसके अलावा गोली और छर्रे के बीच जो एक भ्रम था, वह जांच अधिकारी द्वारा स्पष्ट किया गया है। केवल इसलिए कि डॉक्टर द्वारा निकाली गई गोली को रासायनिक जांच के लिए नहीं भेजा गया था, यह एक ऐसा कारक नहीं होगा जो चश्मदीद गवाहों की गवाही के मूल्य से अधिक है। अभियोजन पक्ष के बयान के अनुसार आरोपी द्वारा घटना के दौरान लगी चोटों का पता नहीं चला है। अभियोजन पक्ष के किसी भी गवाह को बचाव पक्ष के बयान के बारे में कोई सुझाव भी नहीं दिया गया था और पहली बार धारा 313 Cr.P.C के तहत बयान देते समय यह बाते प्रकाश में आई।

हम सब पहले अभियुक्त पर आई चोटों के गैर-स्पष्टीकरण के प्रश्न पर विचार करेंगे- मुद्दा यह है कि यदि ऐसा कोई स्पष्टीकरण नहीं है तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? हम इस बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता से सहमत होने के लिए तैयार नहीं हैं कि प्रत्येक मामले में जहां अभियोजन पक्ष व्याख्या करने में विफल रहता है वहा केवल अभियुक्त को लगी चोटों के कारण अभियोजन पक्ष के मामले को बिना किसी आगे की जांच के स्वतः ही खारिज कर दिया जाना चाहिए। *मोहर राय और भरत राय बनाम बिहार राज्य,* [1968] 3 एस. सी. आर. 525. यह देखा गया कि

> "हमारे फैसले में, अभियोजन पक्ष की उस संबंध में कोई स्पष्टीकरण देने में विफलता से पता चलता है कि अभियोजन पक्ष का सबूत, घटना से संबंधित गवाह, सच नहीं हैं या किसी भी तरह से पूर्ण सच नहीं हैं। इसके अलावा उन चोटो द्वारा ली गई याचिका की संभावना बढ़ जाती है।"

एक अन्य महत्वपूर्ण मामले में *लक्ष्मी सिंह वगैरह बनाम बिहार राज्य,* [1976] 4 एस. सी. सी. 394, मोहर राय (ऊपर) के मामले में निर्धारित अनुपात का उल्लेख करने के बाद इस न्यायालय ने टिप्पणी कीः

"जहाँ अभियोजन पक्ष चोटों की व्याख्या करने में विफल रहता है।" दो परिणाम निम्नलिखित हैं:

(1) यह कि अभियोजन पक्ष के गवाहों का साक्ष्य असत्य है और (2) कि चोटों से याचिका की संभावना बढ़ जाती है।

यह आगे देखा गया कि-

"हत्या के मामले में, घटना के समय या विवाद के दौरान आरोपी को लगी चोटों का स्पष्टीकरण न देना एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण परिस्थिति है जिससे न्यायालय निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकता है।"

(1) कि अभियोजन पक्ष ने घटना की उद्गम ओर उत्पत्ति को दबा दिया है और घटना की उत्पत्ति के विषय में सच्चा संस्करण प्रस्तुत नहीं किया है।

(2) कि जिन गवाहों ने अभियुक्त पर चोटों की उपस्थिति से इनकार किया है, उनके द्वारा मुख्य बिंदुओ पर झूठ बोला जा रहा है अतः साक्ष्य अविश्वसनीय है;इसलिए, उनके बयान पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।

(3) बचाव संस्करण जो अभियुक्त के व्यक्ति पर चोटों की व्याख्या करता है तो यह बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। जहाँ साक्ष्य में इच्छुक या शत्रुतापूर्ण गवाह होते हैं या जहाँ बचाव पक्ष एक ऐसा संस्करण देता है जो प्रतिस्पर्धा करता है।

मोहर राय के मामले (ऊपर) में यह स्पष्ट किया गया है कि अभियुक्त पर पाई गई चोटों के बारे में कोई स्पष्टीकरण देने के लिए अभियोजन पक्ष यह दिखा सकता है कि घटना से संबंधित साक्ष्य सच नहीं है या किसी भी तरह से पूरी तरह से सच नहीं है। इसी तरह *लक्ष्मी सिंह* के मामले (ऊपर) में यह देखा गया है कि अभियोजन पक्ष द्वारा आरोपी को लगी चोटों का कोई भी गैर-स्पष्टीकरण अभियोजन मामले को प्रभावित कर सकता है। लेकिन इस तरह की गैर व्याख्या अधिक महत्वपूर्ण हो सकती है जहां बचाव एक संस्करण देता है जो अभियोजन पक्ष के साथ संभावना में प्रतिस्पर्धा करता है। लेकिन जहां साक्ष्य स्पष्ट, ठोस और विश्वसनीय है और जहां न्यायालय सत्य को झूठ से अलग कर सकता है. केवल यह तथ्य कि अभियोजन पक्ष द्वारा चोटों की व्याख्या नहीं की गई है, ऐसे साक्ष्य को अस्वीकार करने का एकमात्र आधार नहीं हो सकता है, और इसके परिणामस्वरूप पूरा मामला प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। इन पहलुओं को इस न्यायालय द्वारा *विजयी सिंह* वगैरह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य A.I.R (1990) एस.सी. 1459 के मामले में उजागर किया गया था।

अभियोजन पक्ष द्वारा चोटों का गैर-स्पष्टीकरण अभियोजन को प्रभावित नहीं करेगा- जहां अभियुक्त को मामूली और सतही चोटें लगी हैं या जहां साक्ष्य इतना स्पष्ट और ठोस है, इतना स्वतंत्र और उदासीन, इतना संभावित, सुसंगत और विश्वसनीय है, कि यह चोटों की व्याख्या करने के लिए अभियोजन पक्ष की ओर से चूक के प्रभाव का आकलन करता है। जैसा कि इस न्यायालय ने *रामलगन सिंह बनाम बिहार राज्य,* ए. आई. आर. (1972) एस. सी. 2593 के वाद में कहा है। अभियोजन को सभी मामलों में अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा प्राप्त चोटों की व्याख्या करने के लिए नहीं बुलाया जाता है । अभियुक्त व्यक्तियों की चोटों के बारे में अभियोजन पक्ष के गवाहों

से सवाल पूछना बचाव पक्ष का काम है। जब ऐसा नहीं किया जाता है, तो अभियोजन पक्ष के गवाहों के लिए किसी आरोपी के व्यक्ति पर किसी भी चोट की व्याख्या करने का कोई अवसर नहीं होता है। *हरे कृष्ण सिंह वगैरह बनाम बिहार राज्य*, ए. आई. आर. (1988) एस. सी. 863 में यह मत व्यक्त किया गया कि एक ही घटना में अभियुक्त को लगी चोटों की व्याख्या करने का अभियोजन पक्ष का दायित्व प्रत्येक मामले में उत्पन्न नहीं हो सकता है। दूसरे शब्दों में, यह एक अपरिवर्तनीय नियम नहीं है कि अभियोजन पक्ष को उसी घटना में अभियुक्त को लगी चोटों की व्याख्या करनी होगी। यदि अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित गए गवाहों पर न्यायालय द्वारा विश्वास किया जाता है। उचित संदेह से परे अभियुक्त के अपराध के प्रमाण में न्यायालय अभियुक्त द्वारा की गई चोटों की व्याख्या करने के लिए अभियोजन पक्ष के दायित्व पर सवाल उठेंगे नहीं। जब अभियोजन पक्ष एक निश्चित मामले के साथ आता है कि अपराध अभियुक्त द्वारा किया गया है और अपने मामले को किसी भी घटना से परे साबित करता है। उचित संदेह स्वरूप, अभियोजन पक्ष के लिए यह फिर से समझाना शायद ही आवश्यक हो जाता है कि आरोपी के व्यक्ति को कैसे और किन परिस्थितियों में चोटे आई है। यह सब तब अधिक होता है जब चोटें सरल या सतही प्रकृति की होती है। प्रस्तुत मामले में, मामूली और सतही चोटों पर अभियुक्तों की सच्चाई पर संदेह करने के लिए उन्हें बहुत कम सहायता मिलती है।

जहां तक खाट से खून न एकत्रित करने का सवाल है, जांच अधिकारी ने कहा है कि उन्हें घटना स्थल पर खून से सना मिट्टी मिला और उन्होंने उसे जब्त कर लिया था। केवल इसलिए कि इसे रासायनिक जांच के लिए नहीं भेजा गया था, यह जांच में एक दोष हो सकता है लेकिन चश्मदीद गवाहों के साक्ष्य मूल्य को नष्ट नहीं करता है। जाँच अधिकारी को खाट पर खून नहीं मिला। निचली अदालत और उच्च न्यायालय ने इस पहलू का विश्लेषण किया। यह पाया गया है कि गोली लगने के बाद मृतक आगे झुक गया और जो भी खून निकला था वह जमीन पर गिर गया।

जहाँ तक गोली को रासायनिक परीक्षण के लिए नहीं भेजे जाने का प्रभाव है, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि *सुखवंत सिंह* का मामला (ऊपर) इस प्रस्ताव का अधिकार नहीं है, जैसा कि प्रस्तुत किया गया है कि जब भी एक गोली को रासायनिक परीक्षण के लिए नहीं भेजा जाता है तो अभियोजन पक्ष को विफल होना पड़ता है। उस मामले में एक अभियुक्त को दोषी नहीं ठहराने के लिए इस न्यायालय के साथ जिन कारकों का वजन था, उनमें से अभियोजन पक्ष की हथियार और गोली को बैलिस्टिक जांच के लिए भेजने में विफलता थी। प्रस्तुत मामले में, हथियार जब्त नहीं किया गया था जो की *सुखवंत सिंह* (ऊपर) के मामले में एक महत्वपूर्ण तथ्यात्मक अंतर है। वर्तमान मामले में किसी भी अभियोजन साक्षी को यह सुझाव नहीं दिया गया था कि चोटें अभियुक्त अपीलार्थी द्वारा उसके द्वारा बताए गए तरीके से. लगी थी, जैसा कि धारा 313 Cr.P.C के तहत बयान में पहली बार कहा गया है।

जहाँ तक गोली और छर्रे से संबंधित भ्रम का सवाल है, डॉक्टर के साक्ष्य से यह स्पष्ट हो गया। डॉक्टर (पीडब्लू-3) ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मृतक पर केवल एक चोट थी। मृतक का शरीर और मृतक के व्यक्ति पर कहीं भी कोई अन्य चोट नहीं मिली। इसलिए, जांच अधिकारी द्वारा बरामद किए गए पैलेट से मृतक को कोई चोट लगने का सवाल स्थापित नहीं हुआ है। जाँच अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि गोली डॉक्टर द्वारा पुलिस अधिकारियों को दी गई थी जिसे शुरू में पेश नहीं किया गया था क्योंकि यह मालखाने में थी, लेकिन बाद में गवाह को पुनः बुलाया गया और इसे अदालत में पेश किया गया।

हालांकि इसका कोई निर्धारक मूल्य नहीं हो सकता है, निश्चित रूप से गवाहों को दिए गए सुझाव पढ़ना, इसे दिलचस्प बनाते है। पी.डब्ल्यू- 4 से प्रतिपरीक्षा में एक प्रश्न पूछा गया था जो इस प्रकार है।

"x x x x x

यह सही नहीं है कि हीरा, रवींद्र अभियुक्त व्यक्ति को पकड़ने के लिए नहीं भागे, बल्कि वे स्वयं भाग गए।"

यह एक तरह से अभियोजन पक्ष के संस्करण को संभावित बनाता है और किसी भी तरह से रक्षा संस्करण को स्थापित करें जैसा कि पहली बार धारा 313 Cr.P.C के तहत बयान में दिया गया है और इस न्यायालय के समक्ष अभियोजन पक्ष के संस्करण की सत्यता पर संदेह करने के लिए एक आधार होने का अनुरोध किया है।

विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय के सुविचारित निर्णय में किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अपील बिना किसी योग्यता के है और खारिज की जाती है।

अपील खारिज।

R.K.S

अनुवादक- शैलेन्द्र सिंह ADJ.
सत्र न्यायालय, वाराणसी।